दस वर्ष में सरकारी तंत्र में भी चमत्कार होगा

आमोद कुमार
आईएएस
(वर्तमान में विशेष सचिव सूचना प्रौद्योगिकी, उप्र)

बदलता भारत

मेरे सपनों का उत्तर प्रदेश

संदर्भ : सूचना-प्रौद्योगिकी

ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जिसमें आम लोगों को अपनी जरूरतों के लिए सरकारी दफ्तरों में जाना ही न पड़े। उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को लेकर मेरा सपना यही है। दस साल बाद पैदा होने वाले हर व्यक्ति के लिए एक यूनीक आईडी नंबर हो। उसके पास एक कार्ड हो। इस नंबर के जरिए ही वह इण्टरनेट, मोबाइल, लैण्डलाइन और यहाँ तक कि टीवी के जरिए आजीवन वे तमाम काम निपटा सके जिसके लिए उसे अभी सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है। सब कुछ ऑनलाइन। बैंकों को ही लीजिए। खाता खुलवाने के बाद पैसा निकालने के लिए कितने लोग अब बैंक जाते हैं ? एटीएम से सब हो रहा है। दस साल पहले किसी ने सोचा था कि ऐसा भी हो पाएगा ? ऑनलाइन का यही चमत्कार है। मैं अव्यावहारिक सपने नहीं देखना चाहता, लेकिन सरकारी काम-काज में भी ऐसा ही होने के जिस सपने की बात मैं कर रहा हूँ वह दस साल बाद यानी 2017 में उत्तर प्रदेश में हकीकत होगा।

यह सवाल लाजिमी है कि निजी बैंकों ने एटीएम की संस्कृति को विकसित किया। सरकारी सिस्टम में सब कुछ ऑनलाइन संभव ही नहीं, लेकिन सचाई यही है कि सरकार हमेशा निजी क्षेत्र से पीछे ही चलती है। आईटी क्रांति के मामले में भी ऐसा ही होगा। देर होगी, लेकिन काम होगा जरूर। घर-घर कम्प्यूटर होगा। इण्टरनेट का इस्तेमाल बढ़ेगा और साथ ही लोगों की अपेक्षाएँ भी। जन दबाव ही सरकारी सिस्टम में भी दस साल के भीतर यूनीक आईडी नंबर की परिकल्पना को साकार करवा देगा। लोकतंत्र में पॉपुलर पब्लिक डिमांड या कहें जनता की माँग सुने बगैर कोई चारा नहीं। जनप्रतिनिधि भी सुनेंगे और सरकारी सेवक भी। आखिर सरकारी सिस्टम में ही ऑनलाइन टैक्स जमा होने लगा है। रेलवे में कहीं पर भी कहीं के लिए ऑनलाइन रिजर्वेशन होता है। उप्र में भी हाईस्कूल-इण्टर का परीक्षा परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध है। रिजल्ट देखने के लिए अब ब्लैक में अखबार नहीं खरीदना पड़ता। किसी ने कल्पना की थी इसकी ?

जनता के दबाव के अलावा भी बाकी वजहें हैं जो यूपी में यह काम करवाएगी। मसलन, बाकी राज्यों में तेजी से इस दिशा में हो रहा काम, केन्द्र सरकार का दबाव और आईटी को बढ़ावा देने की योजनाएँ और इन सबके अलावा अदालतों से इस दिशा में काम करने के निर्देश भी मिलेंगे। ऑनलाइन में चूँकि सब सामने होगा, यानी पारदर्शी व्यवस्था होगी, तो जिस स्तर पर खामी होगी वह भी सार्वजनिक होगी। यह उस तबके को जरूर पसंद नहीं आएगा जो खामी के लिए जिम्मेदार होगा, लेकिन जनता को यह पसंद आएगा। उसका दबाव भी बढ़ेगा और सिस्टम भी सुधरेगा।

आईटी के इस्तेमाल के मामले में कोई सुधार ही नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं है। आज यूपी में सरकारी व्यवस्था में कम्प्यूटरों पर जितना काम हो रहा है उतना पहले तो नहीं था। यह इस्तेमाल बढ़ रहा है। यह और बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश जैसे व्यापक क्षेत्रफल और ज्यादा आबादी वाले राज्य के लिए तो सरकारी कामकाज में आईटी का अधिकतम इस्तेमाल और जरूरी है। मसलन पश्चिमी उप्र के किसी सरकारी दफ्तर में तैनात किसी अधिकारी या कर्मचारी को लखनऊ या किसी और जिले में काम के सिलसिले में जाने में खासा वक्त लगता है। सब कुछ ऑनलान होगा तो वह अपने दफ्तर में कम्प्यूटर पर बैठ कर काम निपटा सकेगा।

इसी तरह इतनी बड़ी जनसंख्या में एक-एक व्यक्ति का ब्योरा यूनीक आईडी के रूप में दर्ज हो तो जिस काम में अभी खासा वक्त लगता है वह पलक झपकते होगा। एक बात और, आईटी का विस्तार उप्र में रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करेगा। अभी आईटी क्षेत्र में काम करने वालों की जरूरत और उस लिहाज से काम करनेवालों की उपलब्धता में भारी अंतर है। प्रशासनिक सेवाओं में उत्तर प्रदेश के छात्र खासे सफल होते हैं। अगले कुछ वर्षों में आईटी के क्षेत्र में भी ऐसा ही होने के प्रबल आसार हैं। हो सकता है आईटी प्रतिभा के मामले में हम दक्षिण भारत के राज्यों के बराबर खड़े दिखें। इसलिए इस राज्य में आईटी के क्षेत्र में मुझे निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कॉल सेंटरों व बीपीओ की स्थापना की संभावना दिखती है तो सरकारी क्षेत्र में ई गवर्नेंस के सफल इस्तेमाल की। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से उप्र का लगा होना भी यहाँ आईटी के विस्तार की अहम वजह बनेगा। सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक इस्तेमाल एक नई परिकल्पना है इसलिए फैलने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन एक दशक से ज्यादा नहीं। जैसा मैंने पहले कहा कि मैं अव्याहारिक सपने नहीं देखना चाहता, लेकिन बेहद आशावादी जरूर हूँ।

(जैसा रंजीव से कहा)